

सरपंचों के हाथों में गांवों के विकास की बागडोर : भजनलाल शर्मा

बिना भेदभाव सभी विधानसभा क्षेत्रों के गांवों को दिया बजट : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गरीब, किसान और पशुपालकों को मजबूती देकर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह के ग्रामोदय के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर है।



सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायतीराज सशक्तीकरण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया।

कायाकल्प किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों के पास लोगों की सेवा का अवसर होता है और इसी सेवाभाव के साथ राजस्थान के प्रतिभाशाली और समर्पित सरपंच अपने गांवों को विकास की राह पर ले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सरपंच के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर मेरा हृदय आज उसी भाव से भर उठा है, जब मैं स्वयं सरपंच था। उन्होंने कहा कि गांव की मिट्टी में ही पला-बढ़ा है और उसी मिट्टी की सौंधी खुशबू और चुनौतियों के

बीच जिया हूँ। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतीराज के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। हमने राज्य बजट में बिना भेदभाव राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों के लिए बजट का प्रावधान किया। पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2024 से 10 प्रतिशत वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 371 ग्राम पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण करवाया गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए

200 विधान सभा क्षेत्रों में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से मिंसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के 1 हजार 631 कार्य प्रारंभ किए जाकर 530 किलोमीटर लम्बाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों और पशुपालकों के लिए प्राथमिकता के साथ योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पीएम-कृषुसुम योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। किसान अपनी उपपजाऊ भूमि पर सोर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ऊर्जा उत्पादक भी बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार रुपये के अतिरिक्त अनुदान का लाभ भी किसानों को दे रही है। अब तक हम 1355 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जमाबंदी, खसरा गिरावारी और राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा

रही है तथा नामांतरण की प्रक्रिया को बेपररल किया गया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इसके तहत 24 हजार से अधिक गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। पशुपालकों को निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थलाइन कॉल सेंटर सेवा 1962 शुरू की गई है। 536 मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का काम भी हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 72 हजार से अधिक कूपन जारी कर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजीविका परियोजना के तहत 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना साकार हो रहा है।

शिक्षामंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक

जयपुर। शिक्षामंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन व राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के विद्वानों सहित शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धत एवं आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अब तक 12 जिलों का स्थानीय शब्दकोश तैयार किया जा चुका है। अन्य जिलों का शब्दकोश भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने देखी जयपुर फुट की निर्माण विधि



मुख्य सचिव सुधांशु पन्त ने मंगलवार को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) का निरीक्षण किया और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी।

जयपुर (कांस)। मुख्य सचिव सुधांशु पन्त ने मंगलवार को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) का निरीक्षण किया और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी। पन्त ने करीब दो घण्टे तक जयपुर फुट निर्माण से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी ली और और विभिन्न प्ान्तों से आए हुए दिव्यांगों से बातचीत की।

बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डॉ. आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र मेहता और सचिव (तकनीकी) डॉ. दीपेन्द्र मेहता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. बिस्सा ने मुख्य सचिव

सुधांशु पन्त का स्वागत किया। डॉ.आर. मेहता ने पन्त को बताया कि अब तक देश-विदेशों के 22 लाख से अधिक दिव्यांगों को जयपुर फुट लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जयपुर फुट के पदचिह्न 40 देशों में देखे जा सकते हैं, जहां 40 हजार से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया है। पन्त ने बी.एस.वी.एस.एस. द्वारा संचालित फिजियोथैरेपी केन्द्र और उत्तर भारत के सबसे बड़े लकवाग्रस्त मरीजों को पुनर्वास के लिए हाल ही में स्थापित गणपत सरोज सिंघवी रोबोटिक रिहैबिलिटेशन केन्द्र का भी निरीक्षण किया।

घनश्याम तिवारी ने राज्यसभा में उठाया भांकरोटा सड़क दुर्घटना का मामला

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मंगलवार को सदन में दिल्ली-अजमेर बायपास पर गैस से भरे टुक और बस की दुर्घटना के बाद हुए भीषण हादसे के मामले को उठाया। घनश्याम तिवारी ने कहा कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के ब्लास्ट के कारण काफ़ी संख्या में जान माल की हानि हुई। इस घटना में कई निरीक्षकों की जान गयी। इस हादसे में 4 लोग तो मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 8 लोगों ने उसी दिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसा इतना भीषण था कि 5 शवों की पहचान डीएनए सैपल से की गई।
घनश्याम तिवारी ने कहा कि एलपीजी टैंकर के नोजल फटने से गैस

करीब 500 मीटर एरिया तक फैल गई। गाड़ियारों में स्पार्क और अलग-अलग कार्पास से यहाँ मौजूद 40 से ज्यादा गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई थीं। टैंकर के ठीक पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई थी। गैस टैंकर के फटने से न केवल मानव जीवन पर संकट आया, बल्कि आसपास के इलाके में स्थित संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ।
राज्यसभा सांसद तिवारी ने पूरे सदन का ध्यान विषय पर दिलाते कहा कि इस प्रकार की घटना से ना केवल सामाजिक स्थिति पर अपितु सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का मुख्यतः कारण होता है ट्रेफिक को

सुचारु रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाना। जिस स्थान पर यह घटना हुई वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरी तरफ जाने के लिए यू टर्न था वहाँ गैस टैंकर के यू-टर्न के दौरान दूसरे अनियंत्रित वाहन के कारण हादसा हुआ। तिवारी ने समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे स्थानों का चयन करते हुए इन यू टर्न को बंद कराए तथा वैकल्पिक रास्तों का निर्माण हो ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। साथ ही ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील एवं अति -ज्वलनशील की श्रेणी में आते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उचित प्रबंधन तथा संभावित खतरों और उनकी रोकथाम के बारे में इससे जुड़े कर्मचारियों/व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

समरावता उपद्रव प्रकरण में 11 को पेश होगा आरोप पत्र

जयपुर, 4 फरवरी। देवली-उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम से मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने अनुसंधान पूरा कर लिया है। वहीं इस मामले में 11 फरवरी को संबंधित कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश नरेश मीणा की याचिका पर दिया।
गत सुनवाई पर अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से अदालत को

घटना का वीडियो दिखाया था। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि घटना का जिम्मेदार नरेश मीणा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि वह घटना के समय पुलिस अंध्रप्रका में था। ऐसे में वह भीड़ को उपद्रव के लिए कैसे भड़का सकता है। इस मामले में 18 आरोपियों की टोंक के सेशन कोर्ट से और करीब 40 आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है। गौरतलब है कि देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उप चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम से मारपीट की थी। इसके बाद उसके समर्थकों ने उपद्रव फैलाया था। घटना को लेकर पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

108 साधकों ने किया "सूर्य नमस्कार"

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि "सूर्य नमस्कार" भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परम्परा है। यह स्वास्थ्य के लिए वरदान है। उन्होंने



राज्यपाल ने सूर्य सप्तमी पर आयोजित "सूर्य नमस्कार" कार्यक्रम को संबोधित किया।

- 'भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परम्परा "सूर्य नमस्कार" स्वास्थ्य के लिए वरदान'

कहा कि सूर्य नमस्कार मन व शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। बागडे मंगलवार को क्रीडा भारती संगठन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में सूर्य सप्तमी पर आयोजित सांस्कृतिक "सूर्य नमस्कार" कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 108 साधकों ने एक साथ "सूर्य नमस्कार" से जुड़ी योग क्रियाएं कीं। राज्यपाल ने कहा कि योग को

भारतीय परंपरा सूर्य नमस्कार से ही प्रारंभ होती है। यह योग के आगे के आसनो के लिए हमें तैयार करता है। उन्होंने कहा कि "सूर्य नमस्कार" मनुष्य के भीतर की ऊर्जा को संधान कर तन और मन को स्वस्थ करता है। राज्यपाल ने प्रतिदिन हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते समय देवे और

"सूर्य नमस्कार" करने का आह्वान किया। उन्होंने क्रीडा भारती को देश की महत्वपूर्ण संगठन बताते हुए कहा कि पारंपरिक खेलों के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ी इसकी गतिविधियां अनुकरणीय हैं। इस अवसर पर राज्यपाल बागडे ने क्रीडा भारती की स्मारिका "खेल सृष्टि" का भी लोकार्पण किया।

'राजस्थान में रेल अवसंरचना के लिए 9960 करोड़ रु. बजट आवंटित कराया'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 9960 करोड़ रूपए आवंटित करने पर आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि रेल बजट में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ आधुनिकीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इससे यात्री सुविधाओं में बड़ोत्तरी होगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र के उन्माट्टेन्वकर को मजबूत करने की दिशा में रेल मंत्री ने विशेष फोकस किया है। राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित किया जा रहा है। जबकि सुरक्षा के हिंहाज से 10 हजार लोको मोटिव्स में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है।

- सांसद मदन राठौड़ ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया

14.5 गुणा बजट आवंटित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की नीति के आधार पर रेलवे में कार्य किया जा रहा है। रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में रेल मंत्री ने विशेष फोकस किया है। राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित किया जा रहा है। जबकि सुरक्षा के हिंहाज से 10 हजार लोको मोटिव्स में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है।

कार्यकाल पूरा होने के बाद 6759 सरपंचों को प्रशासक किस प्रावधान में लगाया ?

- राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा
- अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि, प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कब कराए जाएंगे और उसका कार्यक्रम क्या है ?

प्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन के जारी कर संविधान व पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पंचायतों को भंग किए बिना ही निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया है। ऐसा करण संविधान के अनुच्छेद 243 ई व 243 के और राजस्थान पंचायत राज एक्ट की धारा 17 व 94 की अवहेलना है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद आम चुनाव नहीं कराना गलत है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ना

तो चुनाव कराए जाने की कोई सीमा तय है और ना प्रशासकों के कार्यकाल की ही कोई तिथि तय की है। जबकि संवैधानिक प्रावधानों में ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ना ही उनमें प्रशासक लगाए जा सकते हैं। वहीं महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के तहत ही सरपंचों को प्रशासक लगाया है। इसके साथ ही महाधिवक्ता ने विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए इस संबंध में जानकारी देने को कहा है।

जयपुर जिले में आज होगा किसान रजिस्ट्री शिविरों का आगाज हर किसान को मिलेगी 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों को अनुपालना में 5 फरवरी से जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन होगा। शिविरों के सफल आयोजन के लिए कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला स्तरीय हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। अपनी ग्राम पंचायत में शिविर के आयोजन सहित अन्य जानकारीयें हासिल करने के लिए आमजन एवं किसान दूरभाष नंबर 0141-2209905, 0141-2209906 पर संपर्क कर सकते हैं।
बुधवार 5 फरवरी को जयपुर जिले के मौजबाबाद के मोसमपुर, किशनगढ़-नेवाल के लुनियाबास,

जयपुर के सुमेल, जोबनर के ढाणी नागान, आमर के लबाना, सांगानेर के गोनेर, फुलेरें-सांभरलेक के हबसपुर, जमवारामगढ़ के भानपुरा कलां, बस्सी के कानोता, कालवाड के बेगस, चौमू के नांगल कलां, शाहपुर के नायन, तुंगा के माधोगढ़, माधोराजपुर के दाबिच, फागी के लदाना, चाकसू के दुटौली, दूढ़ के सुनाडिया सहित कोटखावदा और आंधी ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन होगा।
कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन एवं जिले के समस्त किसानों का एग्रीस्ट्रेक पर रजिस्ट्रेशन

- 31 मार्च तक जयपुर की ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे शिविर

सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये हैं ताकि जिले के प्रत्येक किसान को ना केवल शिविरों के आयोजन की जानकारी हो बल्कि शिविरों में किसान फार्मर आईडी बनाने के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हों सके। एग्रीस्ट्रेक योजनांतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से

31 मार्च तक किया जायेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जायेगी। शिविरों का आयोजन प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जाएगा।
शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुधाम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जायेगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाईल नम्बर की जरूरत होगी।
भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने, प्रधानमंत्री किसान/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी होगी।

सौभाग्य योजना से 2.86 करोड़ घर रोशन किए : मदन राठौड़

जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई "सौभाग्य योजना" के तहत अब तक 2.86 करोड़ घरों को बिजली से रोशन किया गया है। इसके साथ ही दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से देशभर में 18 हजार 374 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। यह जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से राज्यसभा में पूछे गए अतारंकित प्रश्न के जवाब में दी गई है।

- वर्ष 2024 में देशभर में औसतन 21 से 23 घंटे हुई बिजली आपूर्ति - भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

कहा है कि 2014 जब उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली थी तो देश में कुल बिजली उत्पादन 230 गीगावाट था जो अब बढ़कर 462 गीगावाट हो गया है। जिससे देश बिजली की कमी से मुक्त होकर पर्याप्त उपलब्धता की ओर अग्रसर हो रहा है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरगामी निर्णयों के चलते आने वाले वर्षों में औसतन बिजली उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान पर होगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2032 तक देश में तापीय

बिजली के उत्पादन में 80 हजार मेगावाट की बढ़ोतरी हो जाएगी। जिसके तहत वर्ष 2023-24 में 19 हजार 200 मेगावाट बिजली उत्पादन की लिए अनुबंध दे दिए गए हैं। वहीं जलविद्युत उत्पादन में वर्ष 2032 तक 50 हजार 760 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा नवीकरणीय उर्जा के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है जो भविष्य के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बिजली उत्पादन के साथ ही ग्रिड से राज्य और सभी क्षेत्रों में दूर दराज तक बिजली लाईनें डालने के कार्य में भी तेजी आई है। ऐसे में राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार वर्ष 2032 तक एक लाख 91 हजार 474 सीकेएम परेषण लाइनें और 1274 जीवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों से देश और राज्य उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है।